दृष्टि The Vision

करेंट अफेयर्स उत्तराखंड

अगस्त (संग्रह)

2021

दृष्टि, 641, प्रथम तल, डॉ. मुखर्जी नगर, दिल्ली-110009

फोन: 8750187501

ई-मेल: online@groupdrishti.com

अनुक्रम

उत्तराखंड **5**

- उत्तराखंड क्रांति दल (Uttarakhand Kranti Dal-UKD) 5
- आर्किड संरक्षण केंद्र (Orchid Conservation Center) 5
- मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना (Mukhyamantri Vatsalya Yojana) 5
- भारत का पहला भूकंप पूर्व चेतावनी मोबाइल एप 6
- उत्तराखंड की 22 महिलाओं व किशोरियों को तीलू रौतेली सम्मान 6
- ओलंपियन वंदना कटारिया बनी उत्तराखंड के महिला सशक्तीकरण विभाग की ब्रांड एंबेसडर 7
- 'सम्मान पेंशन योजना' 7
- उत्तराखंड सभी सरकारी कॉलेजों को वाई-फाई सुविधा से लैस करेगा 8
- सार्वजनिक परिवहन संचालकों की आजीविका के लिये वित्तीय सहायता 8
- मोबाइल ई-वैन कोर्ट (Mobile e-van court) 8
- लच्छीवाला नेचर पार्क (Lachhiwala Nature Park) 9
- उत्तराखंड के पवनदीप राजन बने 'इंडियन आइडल 12' के विजेता 9
- उत्तराखंड में कक्षा 10 व 12 के छात्रों के लिये मुफ्त टैबलेट 9
- धामी ने शुरू की मुफ्त पैथोलॉजी जाँच योजना 10
- उत्तराखंड में मिली दुर्लभ आर्किड प्रजाति 10

नोट :

- राज्य की महिलाओं के लिये राखी उपहार की घोषणा 10
- महिला स्वयं सहायता समूह 11
- 100% टीकाकरण प्राप्त करने वाला उत्तराखंड का पहला ज़िला 11
- स्पुतनिक-वी वैक्सीन 12
- देश का सबसे ऊँचा औषधि उद्यान 12
- अनुपूरक बजट 13
- गौरा देवी कन्याधन योजना 13
- उत्तराखंड में बिजली, पानी और परिवहन में राहत की घोषणा 13
- माध्यमिक विद्यालयों में व्यावसायिक शिक्षा कार्यक्रम का शुभारंभ 14
- देवभूमि हिमालयन सुपर 30 ट्रस्ट की वेबसाइट का वर्चुअली लोकार्पण 14
- खेल दिवस पर मुख्यमंत्री की घोषणा 15

The Vision

नोट :

दृष्टि
The Vision

नोट :

उत्तराखंड

उत्तराखंड क्रांति दल (Uttarakhand Kranti Dal-UKD)

चर्चा में क्यों ?

- हाल ही में आयोजित उत्तराखंड क्रांति दल के महासम्मेलन में पार्टी के नए अध्यक्ष के तौर पर काशी सिंह ऐरी को चुना गया है।

प्रमुख बिंदु

- उत्तराखंड क्रांति दल का राजनीति से निरंतर पतन होने के कारण यह दल जनता का प्रतिनिधित्व करने में अक्षम बना हुआ है।
- उत्तराखंड निर्माण में सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला यह दल जनता की संवेदनाओं से गहरे तौर पर जुड़ा हुआ है।
- इस दल का गठन वर्ष 1979 में बिपिन चंद्र त्रिपाठी, प्रो. देवीदत्त पंत, इंद्रमणि बड़ोनी व काशी सिंह ऐरी के प्रयासों से हुआ था।

आर्किड संरक्षण केंद्र (Orchid Conservation Center)

चर्चा में क्यों ?

- 30 जुलाई, 2021 को उत्तराखंड के पहले आर्किड संरक्षण केंद्र का चमोली ज़िले के मंडल में उद्घाटन हुआ।

प्रमुख बिंदु

- आर्किड केंद्र बनाने का मुख्य उद्देश्य आर्किड प्रजातियों का संरक्षण करना, पर्यटन को बढ़ावा देना और स्थानीय लोगों के लिये आजीविका के अवसर प्रदान करना है।
- प्रदेश के वन विभाग की अनुसंधान शाखा द्वारा विकसित आर्किड केंद्र को चार भागों- संरक्षण एवं प्रदर्शन क्षेत्र, 1.25 किमी. लंबी आर्किड ट्रेल, इंटरप्रेटेशन केंद्र और आर्किड नर्सरी में बाँटा गया है।
- यहाँ आर्किड की 70 विभिन्न प्रजातियाँ पाई जाती हैं, जिनमें से ज़्यादातर प्रजातियाँ औषधीय गुणों से युक्त और पारिस्थितिकी तंत्र के लिये महत्त्वपूर्ण हैं। इनमें से कई प्रजातियाँ, जैसे- 'लेडीज स्लीपर' (Lady's Slipper) संकटग्रस्त पादपों (threatened category) की श्रेणी में हैं।
- पादप जगत में आर्किड का वही स्थान है, जो प्राणि जगत में बाघ का है। पारिस्थितिकीय परिवर्तन के प्रति आर्किड बहुत संवेदनशील होते हैं और इसलिये किसी पारिस्थितिकी तंत्र के स्वास्थ्य को मापने के लिये इसे एक अच्छा मानदंड माना जाता है।

मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना (Mukhyamantri Vatsalya Yojana)

चर्चा में क्यों ?

- 02 अगस्त, 2021 को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कोरोना काल में बेसहारा हुए बच्चों के लिए 'मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना' का विधिवत् शुभारंभ किया।

प्रमुख बिंदु

- मुख्यमंत्री आवास स्थित जनता दर्शन हॉल में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने डीबीटी द्वारा योजना में चिह्नित बच्चों के बैंक खातों में 3-3 हज़ार रुपए की सहायता राशि ट्रांसफर की।
- इस योजना में आच्छादित बच्चों को 3 हज़ार रुपए प्रतिमाह की आर्थिक सहायता 01 जुलाई, 2021 से 21 वर्ष की आयु तक अनुमन्य की गई है। साथ ही इनके लिये नि:शुल्क राशन, नि:शुल्क शिक्षा की व्यवस्था भी की जा रही है।

नोट :

- ज़िलों के डीएम इन बच्चों की संपत्ति का संरक्षण करेंगे। अनाथ बच्चों के लिए नौकरियों में पाँच प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण की व्यवस्था करने वाला उत्तराखंड पहला राज्य है। सरकार इन बच्चों के कौशल विकास पर भी ध्यान देगी।
- 'मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना' के संचालन हेतु एमआईएस पोर्टल बनाया जा रहा है, जिसमें समस्त बच्चों का विवरण जनपदों द्वारा ऑनलाइन भरा जायेगा।
- इस योजना के तहत 01 अगस्त, 2021 तक जन्म से 21 वर्ष तक की आयु के कुल 2347 बालक/बालिका चिह्नित किये गये हैं। योजना के शुभारंभ के अवसर पर प्रथम चरण में कुल 1062 बच्चों को लाभान्वित किया गया है।

भारत का पहला भूकंप पूर्व चेतावनी मोबाइल एप

चर्चा में क्यों ?

- 04 अगस्त, 2021 को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य में भूकंप में पूर्व चेतावनी प्रदान करने हेतु 'उत्तराखंड भूकंप अलर्ट' (Uttarakhand Earthquake Alert) एप लॉन्च किया।

प्रमुख बिंदु

- यह देश का पहला प्रारंभिक चेतावनी मोबाइल एप्लिकेशन है, जो भूकंप से पहले उपयोगकर्त्ताओं को सचेत कर सकता है।
- इस एप को उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (Uttarakhand State Disaster Management Authority) एवं भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान-रुड़की द्वारा विकसित किया गया है।
- इसके साथ ही उत्तराखंड 'उत्तराखंड भूकंप अलर्ट' नाम से भूकंप अलर्ट एप लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है।
- इस एप की कुछ प्रमुख विशेषताएँ इस प्रकार हैं-
  - यह एप्लिकेशन भूकंप पूर्व चेतावनी (EEW), एक वास्तविक समय भूकंप सूचना प्रणाली का उपयोग करता है, जो भूकंप की शुरुआत का पता लगा सकता है।
  - यह एप भूकंप आने के 30-40 सेकेंड पूर्व भूकंप की पूर्व चेतावनी देगा, जिस हेतु पूरे प्रदेश में लगभग 64 सेंसर लगाए गए हैं।
  - यह एक रिक्टर स्केल पर 5 या अधिक तीव्रता के भूकंप की चेतावनी देने में सक्षम है।
  - एप भूकंप के बाद किसी संरचना के अंदर फंसे लोगों के स्थान को बताने में भी मदद कर सकता है।
  - यह भूकंप की घटना के बारे में जानकारी के साथ-साथ आने वाले संभावित समय और भूकंप के स्थान पर तीव्रता के बारे में जानकारी का प्रसार करता है ताकि किसी भी प्रकार की जनहानि को रोका जा सके।
  - यह एंड्रॉइड और आईओएस दोनों प्लेटफॉर्म के अनुरूप है और दो संस्करणों में उपलब्ध है।
- गौरतलब है कि उत्तराखंड एक भूकंप संभावित राज्य है इसलिये यह एप अधिकारियों को भूकंप के दौरान बचाव अभियान चलाने हेतु महत्त्वपूर्ण योगदान दे सकता है।

उत्तराखंड की 22 महिलाओं व किशोरियों को तीलू रौतेली सम्मान

चर्चा में क्यों ?

- 08 अगस्त, 2021 को उत्तराखंड सरकार ने राज्य की कुल 22 महिलाओं व किशोरियों को 'तीलू रौतेली सम्मान' से सम्मानित किया है।

प्रमुख बिंदु

- उत्तराखंड सरकार द्वारा विभिन्न क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वाली महिलाओं को वीरबाला तीलू रौतेली के नाम पर प्रतिवर्ष यह पुरस्कार दिया जाता है। इसकी शुरुआत 2006 में हुई थी।
- इसके तहत राज्य सरकार 31 हज़ार रुपये व प्रशस्ति पत्र देती है। यह पुरस्कार राशि 2022 से बढ़ाकर 51 हजार रुपये कर दी गई है।

नोट :

- विभिन्न क्षेत्रों के पुरस्कार प्राप्त खिलाड़ी हैं-
  - खेल: वंदना कटारिया (हरिद्वार), रुचि कालाकोटी (बागेश्वर), कनिका भंडारी (अल्मोड़ा)।
  - सामाजिक कार्य: अनुराधा वालिया (देहरादून), उमा जोशी (ऊधमसिंह नगर), दीपिका बोहरा एवं चीपिका चुफाल (पिथौरागढ़), रेनू गड़कोटी (चंपावत)।
  - कोविड संबंधी कार्य: चंद्रकला तिवारी (चमोली), पार्वती किरौला (नैनीताल), बबीता पुनेठा (पिथौरागढ़)।
  - स्वरोजगार: ममता मेहता (बागेश्वर), अंजरा रावत (पौड़ी), भावना शर्मा (अल्मोड़ा)।
  - शिक्षा व महिला जागरुकता: डॉ. राजकुमार भंडारी चौहान (देहरादून)।
  - शिक्षा, अनुसंधान व विकास: डॉ. कंचन नेगी (देहरादून)।
  - महिला स्वास्थ्य व पोषण: नमिता गुप्ता (ऊधमसिंह नगर)।
  - एनजीओ: बिंदुवासिनी (ऊधमसिंह नगर)।
  - पर्वतारोहण: रीना रावत (उत्तरकाशी)।
  - बालिका शिक्षा: रेखा जोशी (पिथौरागढ़)।
  - कठिन परिस्थितियों में जीवनयापन: पूनम डोभाल (टिहरी)।
  - महिला स्व-सहायता समूह: श्यामा देवी (देहरादून)।

ओलंपियन वंदना कटारिया बनी उत्तराखंड के महिला सशक्तीकरण विभाग की ब्रांड एंबेसडर

चर्चा में क्यों ?

- टोक्यो ओलंपिक में भारतीय महिला हॉकी टीम की सदस्य रही उत्तराखंड की वंदना कटारिया को राज्य के महिला सशक्तीकरण विभाग की ब्रांड एंबेसडर बनाया गया है।

प्रमुख बिंदु

- 8 अगस्त, 2021 को आयोजित तीलू रौतेली सम्मान समारोह में राज्य महिला सशक्तीकरण मंत्री रेखा आर्या ने वंदना कटारिया को तीलू रौतेली सम्मान के साथ उक्त विभाग का ब्रांड एंबेसडर बनाया है।
- ध्यातव्य है कि वंदना कटारिया भारत की पहली महिला हॉकी खिलाड़ी हैं, जिन्होंने एक ही मैच में तीन गोल किये।
- वंदना कटारिया उत्तराखंड के रोशनाबाद (हरिद्वार) की निवासी हैं, जो वर्ष 2006 से ही सीनियर महिला हॉकी टीम का हिस्सा हैं।
- उत्तराखंड सरकार ने उनके बेहतरीन प्रदर्शन के लिये उन्हें तीलू रौतेली सम्मान व 25 लाख रुपये देने की घोषणा की है।

'सम्मान पेंशन योजना'

चर्चा में क्यों ?

- 9 अगस्त, 2021 को मुख्यमंत्री धामी ने देहरादून के टाउनहॉल में आयोजित सम्मेलन में राज्य के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों की 'कुटुंब पेंशन योजना' का नाम 'सम्मान पेंशन योजना' कर दिया है।

प्रमुख बिंदु

- स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के बलिदानों के प्रति सम्मान व्यक्त करते हुए इस योजना का नाम सम्मान योजना कर दिया गया है।
- इस अवसर पर स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों को सम्मानित करके उनके योगदान की सराहना की गई।
- इस योजना का मुख्य उद्देश्य स्वतंत्रता सेनानियों के आश्रितों के जीवन स्तर को सुधारना व उन्हें आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना है।

नोट :

उत्तराखंड सभी सरकारी कॉलेजों को वाई-फाई सुविधा से लैस करेगा

चर्चा में क्यों ?

- हाल ही में उत्तराखंड सरकार ने राज्य के सभी सरकारी कॉलेजों को वाई-फाई की सुविधा से लैस करने का निर्णय लिया है।

प्रमुख बिंदु

- राज्य के उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने इस संबंध में एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति का गठन किया है, जो राज्य के 105 सरकारी कॉलेजों में सुविधा स्थापित करने की प्रक्रिया के कार्यान्वयन की निगरानी करेगी।
- समिति का नेतृत्व सूचना प्रौद्योगिकी विकास एजेंसी (आईटीडीए) के निदेशक करेंगे और इसमें निदेशक, उच्च शिक्षा या उनके नामित, संयुक्त सचिव/उपसचिव स्तर के अधिकारी और आईटीडीए के दो तकनीकी विशेषज्ञ शामिल होंगे।
- आईटीडीए के निदेशक आशीष श्रीवास्तव की अध्यक्षता में एक समिति वाई-फाई कनेक्टिविटी स्थापित करने के लिये खरीद की प्रक्रिया को पूरा करेगी और एक कार्य निष्पादन एजेंसी का चयन करेगी।
- निष्पादन एजेंसी उक्त प्रक्रिया को उच्च शिक्षा विभाग को सौंप देगी। उच्च शिक्षा विभाग द्वारा निष्पादन एजेंसी को कार्यादेश दिया जाएगा। इन सभी कार्यों का पूरा खर्च उच्च शिक्षा विभाग द्वारा वहन किया जाएगा।

सार्वजनिक परिवहन संचालकों की आजीविका के लिये वित्तीय सहायता

चर्चा में क्यों ?

- हाल ही में उत्तराखंड के राज्य परिवहन विभाग ने राज्य भर में पंजीकृत सार्वजनिक परिवहन ऑपरेटरों, कंडक्टरों और सफाईकर्मियों, प्रत्येक को 2,000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान करने का निर्णय लिया है।

प्रमुख बिंदु

- राज्य परिवहन सचिव रंजित सिन्हा ने बताया कि राज्य सरकार इस वर्ष कोविड-कर्फ्यू के कारण प्रभावित सार्वजनिक परिवहन संचालकों की आजीविका के लिये वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु मुख्यमंत्री राहत कोष से 12,388.20 लाख रुपये खर्च करेगी।
- मैक्सी कैब, इलेक्ट्रिक रिक्शा, विक्रम, ऑटोरिक्शा और बसों [उत्तराखंड परिवहन निगम (यूटीसी) की बसों को छोड़कर] सहित सभी सार्वजनिक परिवहन के संचालकों को अगले छह महीनों के लिये यह वित्तीय सहायता मिलेगी।
- सिन्हा ने बताया कि विभाग इस पैसे को क्षेत्रीय परिवहन अधिकारियों और ज़िलाधिकारियों के माध्यम से लाभार्थियों के बैंक खातों में स्थानांतरित करेगा।

मोबाइल ई-वैन कोर्ट (Mobile e-van court)

चर्चा में क्यों ?

- 15 अगस्त, 2021 को देश के 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर उत्तराखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश राघवेंद्र सिंह चौहान ने मोबाइल ई-वैन कोर्ट का शुभारंभ किया।

प्रमुख बिंदु

- उत्तर भारत में मोबाइल कोर्ट की शुरुआत अपनी तरह की पहली होगी।
- पहले चरण में उत्तराखंड के पाँच ज़िलों- पिथौरागढ़, चंपावत, उत्तरकाशी, टिहरी और चमोली में मोबाइल ई-कोर्ट शुरू किये जाएंगे।
- इस तरह की मोबाइल अदालतें उत्तराखंड की भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए मामलों के त्वरित निस्तारण में मददगार साबित होंगी।

नोट :

लच्छीवाला नेचर पार्क (Lachhiwala Nature Park)

चर्चा में क्यों ?

- 14 अगस्त, 2021 को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में लच्छीवाला नेचर पार्क का उद्घाटन किया।

प्रमुख बिंदु

- उन्होंने पार्क की सराहना करते हुए कहा कि नेचर पार्क पर दूसरे चरण के काम के लिये बजटीय प्रावधान किया जाएगा।
- इस अवसर पर लेज़र और साउंड शो का आयोजन तथा अमृत महोत्सव गीत का विमोचन भी किया गया।
- राज्य के वन मंत्री हरक सिंह रावत ने कहा कि लच्छीवाला नेचर पार्क अद्वितीय है एवं पूरे भारत एवं विदेशों से पर्यटकों को आकर्षित करेगा।

उत्तराखंड के पवनदीप राजन बने 'इंडियन आइडल 12' के विजेता

चर्चा में क्यों ?

- 15 अगस्त, 2021 को संपन्न हुए सिंगिंग रियलिटी शो 'इंडियन आइडल 12' के ग्रैंड फिनाले मंय उत्तराखंड के पवनदीप राजन विजेता बने। उन्हें पुरस्कारस्वरूप लग्जरी कार और 25 लाख रुपए मिले।

प्रमुख बिंदु

- उत्तराखंड के चंपावत निवासी पवनदीप को संगीत विरासत में मिला है। उनके पिता सुरेश राजन और ताऊ सतीश राजन ने उन्हें संगीत सिखाया है।
- उनके पिता सुरेश राजन कुमाऊँ के मशहूर लोकगायक हैं तथा दादाजी स्व. रति राजन भी प्रसिद्ध लोकगायक थे।
- पवनदीप की नानी भी लोकगायिका थीं। पवनदीप की बहन ज्योतिदीप भी एक गायिका हैं।
- पवनदीप राजन गीत गाने के साथ ही विभिन्न तरह के म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाने में माहिर हैं।

उत्तराखंड में कक्षा 10 व 12 के छात्रों के लिये मुफ्त टैबलेट

चर्चा में क्यों ?

- 15 अगस्त, 2021 को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राज्य के कक्षा 10 और 12 के छात्रों के लिये मुफ्त टैबलेट के वितरण सहित कई घोषणाएँ की।

प्रमुख बिंदु

- देहरादून में पुलिस लाइन पर तिरंगा फहराने के बाद मुख्यमंत्री ने स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि देते हुए यह घोषणा की।
- उन्होंने पर्यावरण और प्रकृति संरक्षण के क्षेत्र में विशिष्ट कार्यों के लिये प्रसिद्ध पर्यावरणविद् सुंदरलाल बहुगुणा के नाम पर 'सुंदरलाल बहुगुणा प्रकृति संरक्षण पुरस्कार' की स्थापना करने और राज्य में भूमि कानूनों के बारे में आशंकाओं को दूर करने के लिये एक उच्चस्तरीय समिति गठित करने की भी घोषणा की।
- साथ ही टोक्यो ओलंपिक में महिला हॉकी में शानदार प्रदर्शन करने वाली वंदना कटारिया की सफलता से उत्साहित होकर खेल के क्षेत्र में उभरती प्रतिभाओं को समर्थन और पोषण देने के लिये एक नई खेल नीति तैयार करने की भी घोषणा की।
- इसी के साथ उन्होंने पवेलियन ग्राउंड से भाजपा युवा मोर्चा द्वारा आयोजित 'देश के लिये दौड़'(एक दौड़ देश के नाम) को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।

नोट :

धामी ने शुरू की मुफ्त पैथोलॉजी जाँच योजना

चर्चा में क्यों ?

- 17 अगस्त, 2021 को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य के लोगों के लिये दीन दयाल उपाध्याय अस्पताल (कोरोनेशन) में मुफ्त पैथोलॉजी परीक्षण योजना की शुरुआत की।

प्रमुख बिंदु

- यह योजना सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल के तहत शुरू की गई है।
- इसके तहत राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) द्वारा उपलब्ध कराई गई धनराशि से राज्य के सरकारी अस्पतालों में 207 प्रकार के पैथोलॉजिकल परीक्षण नि:शुल्क किये जाएंगे।
- यह योजना दो चरणों में लागू की जाएगी। पहले चरण में यह योजना छह ज़िलों- अल्मोड़ा, टिहरी, देहरादून, नैनीताल, हरिद्वार और ऊधमसिंह नगर के 38 ज़िला उप-अस्पतालों और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में शुरू होगी। दूसरे चरण में शेष ज़िलों में नि:शुल्क पैथोलॉजी जाँच योजना लागू की जाएगी।

उत्तराखंड में मिली दुर्लभ आर्किड प्रजाति

चर्चा में क्यों ?

- हाल ही में भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण द्वारा भारत में पहली बार उत्तराखंड के चमोली ज़िले के मंडल क्षेत्र में आर्किड की एक दुर्लभ प्रजाति की खोज की पुष्टि की गई है।

प्रमुख बिंदु

- सेफलांथेरा इरेक्टा वर. ओब्लानसेवलाटा नामक आर्किड की इस प्रजाति को वन विभाग की अनुसंधान विंग ने चमोली ज़िले के मंडल क्षेत्र में ह्यूमस समृद्ध बांज-बुरांस (रोडोडेंड्रॉन-ओक) के जंगलों में 1870 मीटर की ऊँचाई पर खोजा।
- हालाँकि, इस प्रजाति को मई 2021 में ही खोजा गया था, लेकिन भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण (बीएसआई) ने हाल ही में इसकी पुष्टि की है। अब इसे भारतीय वनस्पतियों की सूची के नए संस्करण के रूप में बीएसआई की ओर से आधिकारिक तौर पर मान्यता दी गई है। बीएसआई ने नेलुम्बो पत्रिका के अपने नए संस्करण में सेफलांथेरा इरेक्टा को जोड़ने की पुष्टि की है।
- मुख्य वन संरक्षक (अनुसंधान) संजीव चतुर्वेदी ने बताया कि रेंज ऑफिसर हरीश नेगी और जूनियर रिसर्च फेलो मनोज सिंह ने इसकी खोज की है। ये स्थलीय ऑर्किड मंडल में फूलों की खोज के दौरान मिट्टी पर उगते पाए गए थे।
- ज़मीन पर पाए जाने वाली आर्किड की यह प्रजाति पाँच से 20 सेंटीमीटर तक लंबी होती है और इस पर मई-जून में सफेद रंग के सुंदर पुष्प खिलते हैं।
- यह प्रजाति जापान, चीन और नेपाल के बाद अब भारत में पाई गई है।
- गौरतलब है कि हाल ही में चमोली ज़िले के गोपेश्वर के समीप खल्ला गाँव में स्थापित उत्तर भारत का पहला आर्किड संरक्षण केंद्र जनता को समर्पित किया गया है।

राज्य की महिलाओं के लिये राखी उपहार की घोषणा

चर्चा में क्यों ?

- 19 अगस्त, 2021 को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खटीमा में आयोजित रक्षाबंधन कार्यक्रम में राज्य की आशा और आँगनबाडी कार्यकर्त्ताओं तथा सभी महिलाओं के लिये राखी उपहार की घोषणा की।

नोट :

प्रमुख बिंदु

- उपहारस्वरुप रक्षाबंधन के मौके पर राज्य की आशा और आँगनबाडी कार्यकर्त्ताओं को एक हज़ार रुपए का तोहफा दिया जाएगा और इस दिन सभी महिलाओं को उत्तराखंड रोडवेज की बसों में मुफ्त में सवारी की अनुमति होगी।
- कार्यक्रम में बड़ी संख्या में मुख्यमंत्री के विधानसभा क्षेत्र की महिलाओं ने धामी की कलाई पर राखी बाँधी।
- कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने बहुउद्देशीय शिविरों का आयोजन करने और लोगों की समस्याओं के शीघ्र निराकरण के लिये तहसील दिवस कार्यक्रम आयोजित करने हेतु अधिकारियों को निर्देश दिये।

महिला स्वयं सहायता समूह

चर्चा में क्यों ?

- हाल ही में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने महिला स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) और राज्य सरकार की स्वरोज़गार योजनाओं से जुड़े लोगों के लिये 118.35 करोड़ रुपए के राहत पैकेज की घोषणा की।

प्रमुख बिंदु

- इस पैकेज से उत्तराखंड राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन से जुड़ी महिला एसएचजी के 7,54,984 लोगों को मदद मिलेगी।
- ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत राज्य के 159 क्लस्टरस्तरीय फाउंडेशन (सीएलएफ) मं8 से प्रत्येक को पाँच लाख रुपए का एकमुश्त अनुदान दिया जाएगा।
- इसी प्रकार सक्रिय स्वयं सहायता समूहों को अगले छह महीनों के लिये वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। इसके तहत 42,989 समूहों को 2,000 रुपए प्रतिमाह की राशि दी जाएगी।
- मुख्यमंत्री सौर स्वरोज़गार योजना के ऋण खाताधारकों को इस अवधि के दौरान किये गए ब्याज के लिये मुआवज़ा प्रदान किया जाएगा।
- प्रांतीय विकास दल एवं युवा कल्याण के युवा मंगल दल को छह माह के लिये दो हज़ार रुपए प्रतिमाह की आर्थिक सहायता दी जाएगी।

100% टीकाकरण प्राप्त करने वाला उत्तराखंड का पहला ज़िला

चर्चा में क्यों ?

- 18 अगस्त, 2021 को ज़िला बागेश्वर शत-प्रतिशत टीकाकरण का लक्ष्य हासिल करने वाला देश का दूसरा और उत्तराखंड का पहला ज़िला बन गया। केरल का वायनाड ज़िला 100 प्रतिशत टीकाकरण हासिल करने वाला देश का पहला ज़िला है।

प्रमुख बिंदु

- मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य सचिवालय में पत्रकारों से बातचीत करते हुए खुद बागेश्वर ज़िले की उपलब्धि घोषित की।
- उन्होंने बताया कि पौड़ी के खिर्सू प्रखंड ने भी वयस्क आबादी का शत-प्रतिशत टीकाकरण लक्ष्य हासिल कर लिया है। बागेश्वर ज़िले में 1,76,776 लाभार्थियों को टीके की पहली खुराक मिली है, जबकि पौड़ी के खिर्सू प्रखंड में 37,789 लाभार्थियों को पहली खुराक मिली है।
- धामी ने बताया कि राज्य में टीकाकरण अभियान को गति देने के लिये राज्य, ज़िला और प्रखंड स्तर पर आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं।
- गौरतलब है कि राज्य में अब तक 45 वर्ष से अधिक आयु के 83 प्रतिशत लोगों को पहली खुराक मिली है, जबकि 48 प्रतिशत ने दोनों खुराक प्राप्त की हैं। वहीं 18 से 44 वर्ष की आयु के 61 प्रतिशत लोगों ने पहली खुराक प्राप्त की है, जबकि 4 प्रतिशत ने दोनों खुराक प्राप्त की हैं।
- राज्य में कुल 56,61,943 लोगों को पहली खुराक मिली है, जो कुल वयस्क आबादी का 73 प्रतिशत है।

नोट :

स्पुतनिक-वी वैक्सीन

चर्चा में क्यों ?

- 22 अगस्त, 2021 को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून स्थित ग्राफिक एरा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज द्वारा शुरू की गई स्पुतनिक-वी टीकाकरण सेवा का उद्घाटन करते हुए राज्य में पहली बार स्पुतनिक-वी वैक्सीन को लॉन्च किया।

प्रमुख बिंदु

- लॉन्च कार्यक्रम में कुल 100 लोगों को स्पुतनिक-वी वैक्सीन दी गई। ग्राफिक एरा ग्रुप के मुख्य संरक्षक आरसी घनशाला ने स्पुतनिक-वी वैक्सीन की पहली डोज ली।
- ग्राफिक एरा अस्पताल के प्रधान चिकित्सा अधिकारी डॉ. अजय पटेल ने कहा कि स्पुतनिक-वी वैक्सीन को कोविड-19 के खिलाफ 95 प्रतिशत प्रभावी घोषित किया गया है और डेल्टा संस्करण के मामले में यह टीका लगभग 83 प्रतिशत प्रभावी माना जाता है।
- कोविन ऐप पर पंजीकरण के बाद कोई भी व्यक्ति सरकार द्वारा निर्धारित शुल्क पर ग्राफिक एरा अस्पताल में स्पुतनिक-वी का टीका लगवा सकता है।
- राज्य के स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने बताया कि राज्य में बागेश्वर शत-प्रतिशत टीकाकरण प्राप्त करने वाला पहला ज़िला, जबकि खिर्सू पहली खुराक का शत-प्रतिशत टीकाकरण प्राप्त करने वाला पहला ब्लॉक बन गया है।
- गौरतलब है कि उत्तराखंड में अब तक 58 लाख से अधिक लोगों को कोविड-19 टीकाकरण की पहली खुराक मिल चुकी है, जबकि दोनों खुराक प्राप्त करने वालों की संख्या 18 लाख से अधिक है।

देश का सबसे ऊँचा औषधि उद्यान

चर्चा में क्यों ?

- 21 अगस्त, 2021 को उत्तराखंड के चमोली ज़िले में भारत-चीन सीमा के समीप स्थित माणा गाँव में 11,000 फीट की ऊँचाई पर भारत के सबसे ऊँचे औषधि उद्यान का उद्घाटन किया गया।

प्रमुख बिंदु

- उत्तराखंड वन विभाग की अनुसंधान शाखा ने माणा वन पंचायत द्वारा दी गई तीन एकड़ से अधिक की ज़मीन पर उद्यान का विकास किया है। इस औषधि उद्यान में हिमालयी क्षेत्र के ऊँचाई वाले अल्पाइन क्षेत्र की औषधीय महत्त्व वाली करीब 40 प्रजातियों को सरक्षित किया गया है।
- अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ (IUCN) की रेड लिस्ट के अनुसार, इनमें से कई प्रजातियाँ संकटग्रस्त हैं। साथ ही राज्य जैव विविधता बोर्ड की लुप्तप्राय प्रजातियों की सूची में शामिल हैं।
- यह उद्यान चार वर्गों में विभाजित है। इसमें पहले वर्ग में बद्रीनाथ (भगवान विष्णु) से जुड़ी प्रजातियाँ बद्री तुलसी, बद्री बेर, बद्री वृक्ष और पवित्र वृक्ष भोजपत्र शामिल हैं।
- दूसरा वर्ग अष्टवर्ग प्रजातियों का है, जो हिमालयी क्षेत्र में पाई जाने वाली आठ जड़ी-बूटियों का समूह है। इनमें रिद्धि, वृद्धि, जीवक, ऋषभक, काकोली, क्षीर काकोली, मैदा और महा मैदा शामिल हैं, जो च्यवनप्राश की महत्त्वपूर्ण सामग्री हैं। इनमें से चार जड़ी-बूटियाँ लिली परिवार की और चार ऑर्किड परिवार की हैं।
- तीसरे वर्ग में हिम कमल की प्रजातियाँ हैं। इनमें ब्रह्म कमल भी शामिल है, जो उत्तराखंड का राजकीय पुष्प है। उद्यान में हिम कमल की अन्य प्रजातियों में फेम कमल, नील कमल और कूट शामिल हैं।
- चौथे वर्ग में अतीश, मीठावीश, वनककड़ी एवं चोरू समेत अल्पाइन प्रजातियाँ हैं और ये सभी महत्त्वपूर्ण औषधीय जड़ी-बूटियाँ हैं तथा इनकी बहुत अधिक मांग रहती है।
- गौरतलब है कि माणा चीन की सीमा से लगे चमोली ज़िले में आखिरी भारतीय गाँव है और यह हिमालय पर स्थित प्रसिद्ध मंदिर 'बद्रीनाथ' के करीब है।

नोट :

अनुपूरक बजट

चर्चा में क्यों ?

- 24 अगस्त, 2021 को उत्तराखंड विधानसभा के मानसून सत्र के दूसरे दिन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 5,720.78 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट पेश किया।

प्रमुख बिंदु

- बजटीय प्रावधानों में राजस्व व्यय के लिये 2,990.53 करोड़ रुपए और पूंजीगत व्यय के लिये 2,730.25 करोड़ रुपए शामिल हैं।
- बजट में कोविड-19 से निपटने और स्वरोज़गार योजनाओं के क्रियान्वयन को सुगम बनाने के लिये विशेष प्रावधान किया गया है।
- बजट आवंटन में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY) के लिये 570 करोड़ रुपए, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) के लिये 449 करोड़ रुपए, जल जीवन मिशन के लिये 401 करोड़ रुपए, कायाकल्प और शहरी परिवर्तन के लिये अटल मिशन (AMRUT) के लिये 137.29 करोड़ रुपए, प्रधानमंत्री आवास योजना के लिये 70.01 करोड़ रुपए और स्वच्छ भारत मिशन के लिये 24.65 करोड़ रुपए शामिल हैं।
- कोविड-19 के लिये विभिन्न कार्यों और सहायता हेतु 600 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है, जबकि मुख्यमंत्री स्वरोज़गार योजना (MSY) के लिये 100 करोड़ रुपए, मुख्यमंत्री सौभाग्यवती योजना के लिये 8.34 करोड़ रुपए और मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना के लिये 7.65 करोड़ रुपए आवंटित किये गए हैं।
- इसके अलावा सड़कों और पुलों की मरम्मत तथा रखरखाव के लिये 55 करोड़ रुपए, बाढ़ सुरक्षा कार्यों हेतु 30 करोड़ रुपए, पेयजल परियोजनाओं के लिये 25 करोड़ रुपए और स्मार्ट सिटी परियोजना कार्यों के लिये 60 करोड़ रुपए आवंटित किये गए हैं।

गौरा देवी कन्याधन योजना

चर्चा में क्यों ?

- 24 अगस्त, 2021 को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विधानसभा में घोषणा की कि वर्ष 2015-16 व 2016-17 में गौरा देवी कन्याधन योजना (Gaura Devi Kanyadhan Yojana) के लाभ से वंचित बालिकाओं को सरकार द्वारा योजना का लाभ दिया जाएगा।

प्रमुख बिंदु

- मुख्यमंत्री ने विधानसभा में बताया कि जिन बालिकाओं ने वर्ष 2015-16 व 2016-17 में इस योजना के तहत आवेदन किया था तथा उनको इसका लाभ नहीं मिल पाया था, उन्हें इस योजना का लाभ दिया जाएगा। इसके लिये वांछित आवश्यक धनराशि की भी व्यवस्था की जाएगी।
- प्रदेश में वर्ष 2015-16 में 11,300 बालिकाएँ व वर्ष 2016-17 में 21,916 बालिकाएँ योजना के लाभ से वंचित रह गई थीं। इस प्रकार कुल 33,216 बालिकाओं को कन्याधन योजना का लाभ देने के लिये 49.42 करोड़ रुपए की शेष धनराशि सरकार द्वारा प्रदान की जाएगी।
- गौरतलब है कि 'गौरा देवी कन्याधन' योजना उत्तराखंड सरकार द्वारा वर्ष 2006-07 में शुरू की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य उत्तराखंड राज्य की बीपीएल श्रेणी की 12वीं पास सभी बालिकाओं को उच्च स्तर की शिक्षा हेतु प्रेरित करने के लिये प्रोत्साहन राशि प्रदान करना है।

उत्तराखंड में बिजली, पानी और परिवहन में राहत की घोषणा

चर्चा में क्यों ?

- 26 अगस्त, 2021 को उत्तराखंड विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य में बिजली, पानी और परिवहन सहित विभिन्न क्षेत्रों में राहत की घोषणा की।

नोट :

प्रमुख बिंदु

- मुख्यमंत्री ने कहा कि ऊर्जा विभाग के अंतर्गत विद्युत बिलों के फिक्स्ड चार्ज को 3 माह हेतु छूट प्रदान की जाएगी। इससे लगभग 2,24,604 लोग लाभान्वित होंगे, इसी तरह विद्युत बिलों के विलंब भुगतान अधिभार पर 3 माह के लिये छूट प्रदान की जाएगी।
- परिवहन विभाग के अंतर्गत सेवा कर में 6 माह के लिये छूट दी जाएगी। इसमें लाभार्थियों की अनुमानित संख्या 96,380 है। पंजीयन प्रमाण-पत्र, फिटनेस प्रमाण-पत्र, परमिट एवं ड्राइविंग लाइसेंस आदि के नवीनीकरण पर विलंब शुल्क पर 6 माह के लिये छूट प्रदान की जाएगी।
- शहरी विकास विभाग के अंतर्गत पर्यावरण मित्रों को 2000 रुपए की प्रोत्साहन धनराशि 5 माह तक प्रदान की जाएगी। इससे लगभग 8,300 पर्यावरण मित्र लाभान्वित होंगे।
- प्रधानमंत्री स्वनिधि में पंजीकृत सभी लाभार्थियों को 5 माह तक 2-2 हज़ार रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। इसमें लाभार्थियों की अनुमानित संख्या 25,000 है।
- पेयजल विभाग के अंतर्गत राज्य के समस्त जल/सीवर उपभोक्ताओं द्वारा 31 दिसंबर, 2021 तक अवशेष देयों का एकमुश्त भुगतान करने की दशा में विलंब शुल्क की राशि शत-प्रतिशत माफ की जाएगी।

माध्यमिक विद्यालयों में व्यावसायिक शिक्षा कार्यक्रम का शुभारंभ

चर्चा में क्यों ?

- 27 अगस्त, 2021 को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य के 200 राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में व्यावसायिक शिक्षा कार्यक्रम का शुभारंभ किया तथा राज्य के विभिन्न विद्यालयों के छात्र-छात्राओं, अभिभावकों व अध्यापकों से वर्चुअल संवाद भी किया।

प्रमुख बिंदु

- इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने शिवानंद नौटियाल छात्रवृत्ति की राशि को 250 रुपए से बढ़ाकर 1500 रुपए करने और इसके लाभान्वितों की संख्या को 11 से बढ़ाकर 100 करने की घोषणा की। उन्होंने श्रीदेव सुमन राज्य मेधावी छात्रवृत्ति की राशि को 150 रुपए से बढ़ाकर 1000 रुपए करने की भी घोषणा की।
- मुख्यमंत्री ने कहा कि माध्यमिक विद्यालयों में व्यावसायिक शिक्षा कार्यक्रम में 8 ट्रेड प्रारंभ किये गए हैं। इससे हमारे बच्चों का स्किल डेवलपमेंट होगा, जो कि उनके करियर में सहायक होगा।
- उन्होंने कहा कि सरकार राज्य के राजकीय विद्यालयों के 10वीं और 12वीं के छात्र/छात्राओं को प्रीलोडेड कंटेंट के साथ मोबाइल टैबलेट जल्द उपलब्ध कराएगी। 500 विद्यालयों में वर्चुअल क्लास की स्थापना की गई है, जबकि 600 और विद्यालयों में वर्चुअल क्लास प्रस्तावित हैं। सभी विद्यालयों में एनसीईआरटी की पुस्तकें अनिवार्य की गई हैं। 189 अटल उत्कृष्ट विद्यालय सीबीएसई मान्यता के साथ इंग्लिश मीडियम में प्रारंभ किये गए हैं।
- शिक्षा मंत्री अरविंद पांडेय ने कहा कि उत्तराखंड में स्कूल एजुकेशन में विषयवार अध्यापकों की नियुक्ति की गई है, अतिथि शिक्षकों का वेतन 15 हज़ार रुपए से बढ़ाकर 25 हज़ार रुपए करने का निर्णय लिया गया है।
- गौरतलब है कि नीति आयोग द्वारा शैक्षिक गुणवत्ता में उत्तराखंड को चौथे स्थान पर रखा गया है।

देवभूमि हिमालयन सुपर 30 ट्रस्ट की वेबसाइट का वर्चुअली लोकार्पण

चर्चा में क्यों ?

- 27 अगस्त, 2021 को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास में देवभूमि हिमालयन सुपर 30 ट्रस्ट की वेबसाइट https\\www.himalayansuper30.in\ का वर्चुअली लोकार्पण किया।

प्रमुख बिंदु

- सुपर 30 के माध्यम से राज्य के साधनहीन गरीब छात्रों को आवास, भोजन, कोचिंग आदि की नि:शुल्क व्यवस्था कर उन्हें आई.आई.टी. के लिये तैयार करने का प्रयास किया जाएगा। इससे छात्रों को उनकी सफलता की मंजिल तक पहुँचाने में मदद मिलेगी।

नोट :

- उल्लेखनीय है कि राज्य के प्रतिभावान छात्र-छात्राओं की शैक्षिक क्षमता के अनुसार उन्हें तकनीकी शिक्षा के उच्च संस्थानों में प्रवेश हेतु तैयारी के लिये दिसंबर 2020 में तत्कालीन मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के दिशा-निर्देशन में ज़िला प्रशासन अल्मोड़ा द्वारा अल्मोड़ा में प्रदेश के पहले 'द सुपर-30 हिमालयन एजुकेशनल ट्रस्ट' का गठन किया गया था।
- इसमें प्रदेश के सभी विद्यालयों के 10वीं कक्षा की परीक्षा में मैरिट में रहने वाले चार से पाँच छात्रों को प्रदेशस्तरीय प्रवेश परीक्षा के लिये चुना जाएगा। चुने गए छात्रों में प्रवेश परीक्षा के आधार पर टॉप 30 छात्रों को इस संस्थान में प्रवेश दिया जाएगा।
- इस संस्थान का मुख्य उद्देश्य राज्य के गरीब प्रतिभावान बच्चों को भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) में प्रवेश के लिये नि:शुल्क प्रशिक्षण दिया जाना है।

खेल दिवस पर मुख्यमंत्री की घोषणा

चर्चा में क्यों ?

- 29 अगस्त, 2021 को राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा राज्य में खेलों और खिलाड़ियों के विकास के लिये विभिन्न घोषणाएँ की गईं।

प्रमुख बिंदु

- मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि प्रत्येक वर्ष आठ से 14 वर्ष की आयु के 50 लड़कियों और लड़कों का चयन उनकी क्षमता के आधार पर किया जाएगा और उन्हें प्रत्येक वर्ष मुख्यमंत्री खिलाड़ी उत्थान छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी साथ ही खिलाड़ियों का दैनिक भत्ता 225 रुपए निर्धारित किया जाएगा।
- उन्होंने कहा कि ऊधमसिंह नगर ज़िले में महिला खेल महाविद्यालय की स्थापना की जाएगी, जबकि राष्ट्रीय खेलों में भाग लेने वालों को उत्तराखंड राज्य परिवहन निगम की बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा प्रदान की जाएगी। इसके अलावा, कॉलेजों और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में पाँच प्रतिशत खेल कोटा प्रदान किया जाएगा।
- राष्ट्रीय खेलों में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को भी एशियाई खेलों, राष्ट्रमंडल खेलों और ओलंपिक में पदक विजेताओं को प्रदान की जाने वाली सरकारी नौकरी प्रदान की जाएगी।
- इसके साथ ही धामी ने घोषणा की कि खिलाड़ियों के प्रदर्शन के वैज्ञानिक और मनोवैज्ञानिक पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करने के लिये राज्य खेल विकास संस्थान में खेल विज्ञान केंद्र स्थापित किया जाएगा तथा देहरादून के महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज को खेल विश्वविद्यालय बनाने का भी प्रयास किया जाएगा।

नोट :